बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 85

कृषि उपज की चुनौती

प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद कीमत को उसकी उत्पादन लागत के 50 फीसदी तक बढ़ाए जाने के बाद भी जिंस बाजारों में निरंतर गिरावट आ रही है। यह एक ऐसा विषय है जिससे देश की नई सरकार को तत्काल निपटना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वाली अधिकांश जिंस मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन में इन दरों से 10 से 30 फीसदी कम दर पर बिक रही हैं। गत खरीफ सीजन में भी हालात अलग नहीं थे। केवल गेहूं और चावल ही अपवाद हैं जो चुनिंदा क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे जाते हैं। इसके अलावा तुअर, कपास और जौ पर भी यह बात लागू होती है क्योंकि इनकी मांग आपूर्ति से ज्यादा है। हालांकि दाल और तिलहन की खरीद कुछ इलाकों में सरकार द्वारा नियत एजेंसियों द्वारा भी की जाती है लेकिन इस खरीद की मात्रा अत्यंत कम है। यही कारण है कि ये बाजार को प्रभावित नहीं करती। सरकार की प्रमुख मूल्य समर्थन योजना पीएम-आशा (अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) को भी गति नहीं मिल सकी। इस प्रक्रिया में जिन किसानों को नुकसान हुआ है, आशंका है कि नई सरकार के गठन के बाद वे भी विरोध करेंगे।

जिंस कीमतों में मौजूदा गिरावट का काफी श्रेय बीते कुछ वर्ष के दौरान निरंतर अधिशेष उत्पादन को दिया जा सकता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कमजोर जिंस कीमतें और प्रतिकूल घरेलू और बाहरी व्यापार नीतियां भी इसका कारण हैं। इतना ही नहीं पुराने नए घरेलू माल के विपणन के दौरान ही भंडारित माल का निपटान और नए आयात की इजाजत भी इसका कारण है। इससे अलग पीएम आशा योजना में वही मूलभूत कमियां हैं जो अन्य मूल्य समर्थन योजनाओं में। मध्य प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में भावांतर भुगतान का प्रयास किया गया। कुछ जगहों पर तयशुदा कमीशन के आधार पर कृषि उपज की खरीद और प्रबंधन में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने की कोशिश भी की गई। मुख्य उपज खासकर चावल और गेहूं की खुली खरीद का काम दशकों से चल रहा है और इसकी बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है, लेकिन सरकारी खजाने पर इसका भारी बोझ पड़ा है। परंतु यह भी मोटेतौर पर चुनिंदा राज्यों तक सीमित है जहां खरीद का बुनियादी ढांचा मौजूद है। अन्य स्थानों पर गेहूं और चावल की बिक्री एमएसपी से कम दर पर होती है। इस योजना को देश भर की सभी फसलों पर लागू करने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। भावांतर भुगतान योजना भी नाकाम रही है क्योंकि पंजीयन की प्रक्रिया जटिल थी और नियमित मंडियों के जरिए बिक्री करना अनिवार्य था जहां बिचौलिये हावी थे। उपज का अधिकतम 25 फीसदी ही खरीदा जा सकता था। तीसरा विकल्प था मूल्य समर्थन व्यवस्था में निजी कारोबारियों को शामिल करना। यह इसलिए नाकाम रहा क्योंकि खरीद, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, निस्तारण आदि के लिए एमएसपी का केवल 15 फीसदी कमीशन तय किया गया था जो कि बहुत कम था।

इन मसलों को हल करने के अलावा कृषि-जिंस कीमतों में सुधार के लिए कई अन्य कदम उठाने की आवश्यकता है। अधिशेष उपज का निर्यात करने की सुविधा आवश्यक है। इसके लिए आयात-निर्यात शुल्क दरों में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही, कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वे अपनी कृषि में विविधता लाएं और मूल्यवर्धित फसल उगाएं। इससे बिना सरकारी हस्तक्षेप के उनको बेहतर प्रतिफल मिल पाएगा। नीतिगत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसानों के हितों और मुद्रास्फीति के प्रबंधन के बीच संतुलन कायम हो सके।

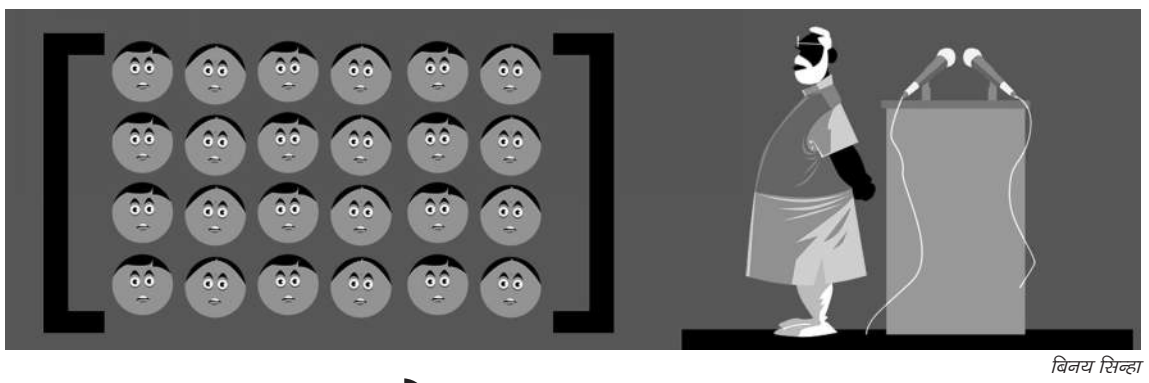

बिनय सिन्हा

मंडल और मंदिर से आगे मोदी की राह

भाजपा की मंदिर की राजनीति ने मोदी-शाह के अधीन आने के बाद मंडल की राजनीति को समाप्त कर दिया और एक देशव्यापी हिंदू वोट बैंक तैयार किया। मोदी को चुनौती देने वाले को नई राजनीति तलाशनी होगी।

चुनाव की बात

शेखर गुप्ता

ठीक तीन दशक बाद भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हुआ और नए युग की शुरुआत हुई। हम नेहरू-गांधी परिवार के पतन और नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय राजनीति के एक नये ध्रुव के आगाज की बात नहीं कर रहे। देश के व्यापक राजनीतिक बदलाव को इस संकीर्ण नजरिये से देखना उचित नहीं होगा। यह मंडल और मंदिर की राजनीति का अंत और मोदी युग की शुरुआत है। सन 1989 में लगभग इसी समय भाजपा की वापसी की संभावनाएं बनी थीं। इससे पहले 1984 में पार्टी दो सीटों पर सिमट गई थी। सन 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व के अंतिम वर्ष में उनके करीबी और रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बगावत कर दी थी और राजीव के स्वाभाविक स्थानापन्न नजर आ रहे थे। परंतु वह बिना भाजपा के सहयोग के ऐसा नहीं कर सकते थे। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी सत्ता में हमेशा के लिए साझेदार भर नहीं बने रहना चाहते थे।

वह चाहते थे कि भाजपा अपने दम पर सत्ता में आए। इसके लिए भाजपा को भ्रष्ट राजीव को हटाने से इतर एजेंडे की तलाश थी। आडवाणी ने अयोध्या का मसला उठाया। उन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद को हिंदू जागरण से मिलाया और इस प्रकार मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। आडवाणी ने राजीव को रोकने में विपक्ष की मदद की। विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल को 143 सीटें मिलीं जिनमें से अधिकांश हिंदी प्रदेश में थीं। सिंह को राष्ट्रीय मोर्चे की नई सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मोर्चा 272 के जादुई आंकड़े से दूर था। यह दूरी पाटने में वाम और भाजपा के बाहरी समर्थन ने मदद की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि ये दो विपरीत विचारधाराएं एक साथ आई थीं।

जनता दल और उसके छोटे सहयोगियों की सीटों में पुराने समाजवादी और कांग्रेस के बागियों का हिस्सा था। वे आमतौर पर भाजपा को पसंद नहीं करते थे। कश्मीर में उभरती अशांति, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के गृहमंत्री और कश्मीरी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण और बदले में कश्मीरी अलगाववादियों की रिहाई की मांग पर झुकने से हालात और खराब हो गए।

सिंह और उनके समाजवादी/ लोहियावादी विचारकों को पता था कि यह साझेदारी अस्थायी है और इसलिए वे कांग्रेस और भाजपा विरोधी नई राजनीति में जुट गए। तब करीब एक दशक पुराने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण से संबंधित थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 22.5 फीसदी आरक्षण से पहले ही नाराज सवर्ण विश्वनाथ प्रताप सिंह से बेहद नाराज हो गए। हिंसात्मक आंदोलन में करीब 159 युवाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया और 63 जानें चली गईं। एक किस्म का जातीय युद्ध छिड़ गया। इस प्रक्रिया में विश्वनाथ प्रताप सिंह और समाजवादियों ने नया ओबीसी वोट बैंक तैयार कर लिया। भाजपा को यह आशंका पैदा हो गई कि इससे उसका हिंदू वोट बंट सकता है। यह वह दौर था जब आडवाणी समूची आबादी को हिंदू-मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रहे थे।

सिंह की मंडल नीति, आडवाणी की मंदिर नीति से टकरा रही थी। मंडल बनाम मंदिर की राजनीति तब से भारतीय राजनीति को परिभाषित करती रही। क्या जातीय विभाजन को आस्था से जोड़ा जा सकता है?

जब भी यह कारगर हुआ, भाजपा सत्ता में आई। परंतु ज्यादातर मौकों पर जातीय समीकरण भारी पड़े। खासकर इसलिए क्योंकि हिंदी क्षेत्र में तमाम नेताओं ने जातीय गोलबंदी की। कांशीराम और मायावती भी इसमें शामिल हो गए और दलित उनके पीछे एकजुट हो गए। मुस्लिम कभी इनकी ताकत बने तो कभी उसका उलट हुआ। दोनों ने मिलकर हिंदी प्रदेश में भाजपा को पराजित किया और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए गठजोड़ किया। वर्ष 2019 के जनमत ने इसका अंत कर दिया। मंडल पर मंदिर को जीत मिली, कहने से बात पूरी नहीं होगी। यह कहना अधिक सही होगा कि मोदी और शाह के अधीन मंदिर ने मंडल को हड़प लिया। मोदी देश के पहले ऐसे पिछड़ा प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। मंडल का वोट बैंक टूट चुका है। मोदी को मंदिर और मंडल दोनों से ताकत मिली है।

यह बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा कैसे हुआ? इसके क्या संभावित परिणाम हैं? इसका प्रतिरोध कैसे होगा और देश की राजनीति में एक नया ध्रुव कैसे बनेगा?

नतीजों की शाम मोदी के पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए भाषण को याद करें, उन्होंने दो बातें कहीं। पहला, देश में केवल दो जातियां हैं एक गरीब और दूसरी वे जो गरीबों की मदद के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम हैं। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लगाने वालों की हार हुई है। राजनीतिक संदेश कहता है कि अब वह समय गया जब जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटा जाता था और मुस्लिम मतों की सहायता से सत्ता पाई जाती थी।

यह केवल मोदी के कारण संभव हुआ। विपक्ष को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। चुनाव पूर्व गठबंधन तब काम करते हैं जब आप किसी विचारधारा या पार्टी से लड़ रहे हों। किसी व्यक्ति से लड़ने में वे काम नहीं आते, खासतौर पर मोदी जैसी लोकप्रियता वाले व्यक्ति से या फिर सन 1971 की इंदिरा गांधी से। मोदी और शाह ने भाजपा को वहां ले जाने का दुस्साहस किया है जहां आडवाणी और उनकी पीढ़ी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मंदिर को लेकर उनके ध्रुवीकरण को हिंदी क्षेत्र के मतदाताओं की उच्च वर्णीय मंडल विरोधी आत्मदाह करने वालों के साथ सहानुभूति में स्पष्ट देखा गया था। मोदी और शाह अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों तक पहुंचने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने मायावती और मुलायम सिंह यादव, दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाई और दोनों जाटव और यादव के रूप में जाति विशेष के नेता बनकर रह गए। अन्य दल भाजपा की ओर झुकते चले गए। पार्टी के पास उच्च वर्ण का हिंदू राष्ट्रवादी वोट बैंक पहले से है। इन अतिरिक्त आंकड़ों ने उसे और ताकतवर बनाया। बिहार गैर भाजपा ओबीसी नेता नीतीश कुमार के पास है, एक अन्य बड़े दलित समूह के नेता राम विलास पासवान भाजपा के साथ हैं। बीते तीन में से दो दशक तक भाजपा को सत्ता से बाहर रखने वाले मंडल की चुनौती 2019 में पूरी तरह समाप्त हो गई।

मोदी के पास अब अवसर है कि वह नई रूपरेखा लिखें। चूंकि अब वह उच्च वर्णीय हिंदुओं की वफादारी को कुछ हल्के में ले सकते हैं इसलिए वह केंद्र और राज्य में ओबीसी और दलित नेताओं को मजबूत बना सकते हैं। बिहार में वह पहले ही मजबूत नेता तैयार कर रहे हैं और आगे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कर सकते हैं। हिंदू उनके नेतृत्व में पर्याप्त सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए वे मुस्लिमों तक भी पहुंच सकते हैं। संदेश है: सारे दलों के मत प्रतिशत मिलाकर सत्ता हासिल करने का वक्त गया। वह राजनीति अब खत्म हो चुकी है इसलिए मेरी छत्रछाया में आइए। आखिरकार, जैसा कि मैंने कहा, भारत में केवल दो जातियां हैं गरीब और संपदा बनाने वाले। अधिकांश मुस्लिम इसमें शामिल नहीं हैं लेकिन कुछ तो हैं। इसे देश में राजनीति का अंत समझना भूल होगी। यह केवल मंडल और मंदिर युग का समापन है। मोदी को चुनौती देने वाले अगले नेता को एक नई राजनीति तलाशनी होगी। कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद होगी कि जाति एक बार फिर आस्था के आधार पर एकजुट लोगों को विभाजित करेगी। परंतु मुझे लगता है कि यह विचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

यह नई राजनीति कौन और कैसे तैयार करेगा? चुनाव नतीजों को खंगालें तो पता चलता है कि भाजपा की 303 और कांग्रेस की 52 सीटों के पीछे दो अहम आंकड़े हैं। भाजपा के वोट 2014 के 17.1 करोड़ से बढ़कर अब 22.6 करोड़ हो गए हैं। कांग्रेस के वोट भी 10.69 करोड़ से बढ़कर 11.86 करोड़ हो गए हैं। वर्ष 2014 में दोनों के बीच कुल 27.79 करोड़ वोट बंटे थे जो अब 34.46 करोड़ हो गए हैं। यह 2014 में कुल वोट के 50.3 प्रतिशत से बढ़कर 57 फीसदी हो गया है। मंडलवादी दलों तथा अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर छिटका वोट वापस राष्ट्रीय दलों की ओर लौट रहा है। इसलिए आप भले ही कांग्रेस को हल्के में ले लें लेकिन मोदी और शाह ऐसा नहीं कर सकते।

इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने की सरकारी पहल

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए तमाम नीतिगत कदम उठाए गए हैं। इन वाहनों के साथ कई लाभ जुड़े हैं। वे शून्य-उत्सर्जन के साथ शोर भी बहुत कम करते हैं। प्रति किलोमीटर उपभोग के संदर्भ में विद्युत ऊर्जा काफी सस्ती पड़ती है। इन वाहनों के इंजन में आंतरिक दहन (आईसी) इंजनों की तुलना में गतिशील हिस्से कम होते हैं। इस वजह से उनका रखरखाव आसान होता है और उनके ठप हो जाने की आशंका कम होती है। हाइब्रिड इंजनों के लिए भी यह बात सही है क्योंकि उसमें आईसी इंजन को कम क्षति होती है।

हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें इनका एक नकारात्मक पहलू है। करों में कटौती के बावजूद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की कीमतें आईसी इंजन वाले वाहनों से काफी अधिक होती हैं। परिचालन लागत कम होने से इसकी थोड़ी भरपाई होती है फिर भी फर्क अधिक है। सुरक्षा का मुद्दा भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने पर उसे बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है। लिथियम-आयन बैटरी की आग बुझाए जाने के कई घंटे बाद भी शॉर्ट-सर्किट होने से दोबारा आग भड़क सकती है। अग्निशमन विभाग को बैटरी चालित वाहनों में लगी आग बुझाने के लिए नए सिरे से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में अधिक वक्त लगता है। यहां तक कि फास्ट रिचार्ज करने में भी कम-से-कम 20 मिनट लग जाते हैं। बैटरी की अदला-बदली एक जल्दबाजी वाला विकल्प है लेकिन वह भी पेचीदा काम है। अलग-अलग वाहनों को अलग तीव्र एवं सुस्त चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत होती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी ढांचागत आधार तैयार करना एक चुनौती है। देश भर में 60,000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं। इससे एक अंदाजा मिलता है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए कितने चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत पड़ेगी? बैटरी चालित वाहनों की सर्विसिंग, रखरखाव और मरम्मत के लिए अपने कर्मचारियों को नए सिरे से प्रशिक्षित करने की भी जरूरत होगी। मार्च 2019 में मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये वाले फेम-2 कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई थी। हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम) के पहले कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल, 2015 को 895 करोड़ रुपये के बजट के साथ हुई थी। दो साल की अवधि वाले फेम-1 कार्यक्रम की मियाद कई बार बढ़ाई गई।

फेम-2 के लिए सरकार ने तीन साल की अवधि तय की है। इसका लक्ष्य 10 लाख दोपहिया, 5 लाख तिपहिया, 55 हजार चार-पहिया और 7,000 बसों को मदद देना है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री निम्न आधार होने से बहुत तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता सोसाइटी का दावा है कि वर्ष 2018-19 में 6.3 लाख इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और 1.26 लाख दोपहिया वाहन और करीब 3,600 यात्री कारों की बिक्री हुई। यह 1.9 करोड़ से अधिक दोपहिया-तिपहिया वाहनों की बिक्री के चार फीसदी से भी कम है और 30 लाख से अधिक कारों के एक फीसदी से भी कम है।

फेम-2 कार्यक्रम के तहत 2019-20 में 1500 करोड़ रुपये, 2020-21 में 5,000 करोड़ रुपये और 2021-22 में 3,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 35,000 चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को 1.5 लाख रुपये और 20,000 हाइब्रिड चार-पहिया वाहनों को 13,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा 7,090 ई-बसों को 50-50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2018 के मसौदे में वर्ष 2023 तक पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों में 25 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों के पहुंचाने का लक्ष्य है और हरेक तीन किलोमीटर पर बैटरी एक्सचेंज सेंटर और चार्जिंग स्टेशन बनाने का उद्देश्य है। दिल्ली में सालाना करीब सात लाख नए वाहनों का पंजीकरण होता है।

दिल्ली की इस नीति में फेम-2 कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के अलावा भी काफी कर-छूट एवं सब्सिडी देने का जिक्र है। एक इलेक्ट्रिक दोपहिया को 22,000 रुपये तक की सब्सिडी देने के अलावा बैटरी बदलने पर भी अलग से सब्सिडी मिलेगी। बीएस-2 या बीएस-3 मानक वाले दोपहिया वाहनों को कबाड़ में देने पर 15,000 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स, पंजीकरण, एमसीडी पार्किंग शुल्कों से छूट मिलती है और ई-ऑटो या ई-कैब के हरेक फेरे पर 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा। दिल्ली सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 1,000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदने जा रही है।

शहरी इलाकों में हरेक तीन किलोमीटर और राजमार्गों पर हरेक 25 किलोमीटर दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन मुहैया कराने का लक्ष्य देखते हुए फेम-2 के तहत चार्जिंग स्टेशनों को लाइसेंस-मुक्त किया गया है। हरेक चार्जिंग स्टेशन पर फास्ट चार्ज और स्लो चार्ज के लिए अलग प्लग-प्वाइंट लगाने की जरूरत होती है।

फास्ट चार्ज सिस्टम में एक कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम और एक चाडेमो प्लग लगा होता है जिसमें 200-1000 वोल्ट के 50 किलोवाट के कनेक्शन होते हैं। वहां 380-480 वोल्ट के 22 किलोवाट क्षमता वाले टाइप-2 एसी फास्ट चार्जर की भी जरूरत होती है। इसके अलावा स्लो चार्जिंग के भी दो प्वाइंट- भारत एसी 001 और भारत डीसी 001 रखने होते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के लिए इनकी कीमतों का कम होना और बैटरियों की लागत में कमी आना जरूरी है। चार्ज स्टेशनों और दक्ष सेवा कर्मचारियों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन इसमें वक्त लगेगा।

मौजूदा रुख के हिसाब से भारत में दोपहिया एवं तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले रफ्तार पकड़ने की संभावना है और किराये की सवारी के तौर पर लोग इनका अधिक इस्तेमाल करेंगे। हालांकि माहौल बदलने और कीमतों में कमी आने पर निजी उपयोग भी बढ़ सकता है।

कानाफूसी

गुटबाजी से हार

हरदीप पुरी जैसे प्रतिभाशाली और बढ़िया मंत्री को अमृतसर से पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? इस सवाल का एकमात्र जवाब गुटबाजी है। अरुण जेटली के बाद पुरी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें इतनी बड़ी मोदी लहर में इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष श्वेत मलिक और पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने सहयोग नहीं किया। अधिकांश पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना रहा कि चूंकि पुरी अमृतसर में बाहरी हैं इसलिए उन्हें जिताने का जिम्मा तो मलिक का था। जैसे ही पुरी के हारने की खबर फैलने लगी, व्हाट्सऐप पर यह संदेश फैलने लगा कि मलिक इस हार के लिए जवाबदेह हैं। होशियारपुर सीट भी इस गुटबाजी का शिकार होते-होते बची। इस सीट के सांसद विजय सांपला को टिकट नहीं मिला था इसलिए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी सोमपाल के पक्ष में प्रचार नहीं किया। वह तो केंद्रीय नेतृत्व ने समय रहते हस्तक्षेप किया और मोदी यहां प्रचार करने पहुंचे। इतना ही नहीं उन्होंने चार केंद्रीय मंत्रियों को इस जगह कैंप करने के लिए भेजा। चारों मंत्री चुनाव समाप्त होने तक यहां बने रहे, तब जाकर पार्टी इस सीट पर जीत सकी।

आपका पक्ष

महिला सांसदों की संख्या बढ़ी

लोकसभा चुनाव में इस बार महिला उम्मीदवारों ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। चुनाव में कुल 78 महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इस बार14 प्रतिशत से अधिक महिलाएं संसद में दिखाई देंगी। यह अबतक के लोकसभा चुनावों के मुकाबले अधिक है। वर्ष 2014 में 66 महिलाएं संसद पहुंची थीं। इस साल चुनाव में सभी दलों और निर्दलीयों को मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या 724 थी। इस बार तमाम पार्टियों ने पहले के मुकाबले महिला उम्मीदवारों पर अधिक विश्वास जताया। इस आम चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली भाजपा ने 54 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिनमें से 34 संसद में जगह बनाने में सफल रहीं। विपक्षी दल कांग्रेस ने 54 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिनमें से अधिकतर को हार का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय दलों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 23 महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया जिनमें 11 उम्मीदवार सफल रहीं। इस सूची में पहली बार चुनाव लड़ रही बांग्ला अभिनेत्री नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर राजनीति में सक्रिय हुई बीजू जनता दल की चंद्रमणि मुर्मू ने महज 25 साल 11 महीने की उम्र में चुनाव जीतकर इस चुनाव में सबसे युवा महिला प्रत्याशी का खिताब जीता। भारत में महिलाओं की संख्या करीब 49 प्रतिशत है। ऐसे में उनकी राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सक्रियता की जरूरत है।

उद्धेश कुमार, मणिपाल

इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश से 78 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली है

मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी

लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से विपक्षी दल मोदी लहर को काटने की बातें करने लगे तो भाजपा ने मोदी लहर को और बढ़ाने की बात कही। विपक्षी दल अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए महागठबंधन बनाया गया। दो धुर विरोधी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया। मतदान शुरू होने के बाद चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए। ईवीएम में गड़बड़ी करने की संभावनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की गई। वीपीपैट पर्ची मिलाने की संख्या बढ़ाये जाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। चुनाव आयोग में आपसी फूट की बातें सामने आने लगी। लेकिन अंतिम परिणाम मोदी के पक्ष में आए। भाजपा को वर्ष 2014 के मुकाबले 2019 में अधिक सीटों पर जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी ने दीर्घकालीन रणनीति बनाई और देश के विकास के लिए स्थिर सरकार की आकांक्षा की। देश की जनता ने इन दोनों चीजों पर अपना विश्वास जताया। मोदी की जीत के पीछे कई कारण हैं। इनमें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत सरकार का संदेश, जातीय समीकरण तोड़ने में सफलता, पूर्वोत्तर में कड़ी मेहनत, दक्षिण में अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश आदि शामिल हैं। मोदी की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ गई है जिस पर पूरे देश ने अपनी मुहर लगाई।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।